जापानी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु इन्वेस्ट यूपी ने जापानी हितधारकों के साथ सहभागिता को किया सुदृढ़

जापान के साथ आर्थिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इन्वेस्ट यूपी के जापान डेस्क ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री शशांक चौधरी के नेतृत्व में जापान स्थित भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख, श्री आर. मधु सूदन के साथ एक रणनीतिक बैठक आयोजित की।

बैठक के दौरान, एसीईओ ने जापानी उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही आउटरीच पहलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यामानाशी प्रीफेक्चरल सरकार, जेईटीआरओ (जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन), आईसीसीजे (इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर इन जापान/इंडो-जापानी चैंबर्स), केपीआईए (कांसाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन्स) सहित प्रमुख जापानी संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग को रेखांकित किया, जो द्विपक्षीय औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने और उभरते क्षेत्रों में निवेशक आवश्यकताओं को सुगम बनाने पर केंद्रित है।

एसीईओ ने दूतावास को अवगत कराया कि ऑटोमोबाइल एवं ओईएम विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी एवं आईटीईएस (जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सम्मिलित हैं) तथा फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों में जापानी कंपनियों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में प्रस्तावित 'जापानी सिटी' पर कार्य प्रगति पर है, जिसे 500 एकड़ में विकसित किए जाने वाले एक समर्पित औद्योगिक एवं आवासीय हब के रूप में परिकल्पित किया गया है, जहां जापानी निवेशकों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और एकीकृत सेवाएं उपलब्ध होंगी।

श्री आर. मधु सूदन ने इन्वेस्ट यूपी के संरचित प्रयासों की सराहना की और जापानी हितधारकों के साथ सहभागिता को और सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने

निवेश प्रोत्साहन की गति बनाए रखने हेतु नियमित फॉलो-अप और सतत सुगमता की आवश्यकता पर जोर दिया।

उप मिशन प्रमुख ने इन्वेस्ट यूपी के सक्रिय दृष्टिकोण की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि ये प्रयास उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देंगे तथा भारत-जापान आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे।